रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2017/माघ 4, 1938
No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2017/MAGHA 4, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 69(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का नाम मूल (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियम, 1922 के नियम 56 में, खंड (घ) में छठे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थातः—

"परंतु शर्त यह है कि पांचवें परंतुक में सन्निहित किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार यदि जनहित में आवश्यक समझती है तो उक्त दो वर्ष की अवधि के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए विदेश सचिव को सेवा विस्तार दे सकती है।"

[फा. सं. 26012/1/2017-स्था. (क-IV)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में 1 जनवरी, 1922 को प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 567(अ), तारीख 31 मई, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2017

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely : –

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2017

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules, 1922, in rule 56, in clause (d), after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided also that notwithstanding anything contained in the fifth proviso, the Central Government may, if considers necessary, in public interest, so to do, give an extension in service for a further period not exceeding one year beyond the said period of two years to the Foreign Secretary".

[F. No. 26012/1/2017-Estt. (A-IV)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

Note: The Fundamental rules were published in the Gazette of India on 1st January, 1922 and were also amended vide notification under G.S.R. 567(E), dated the 31st May, 2016.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.25 23:08:04 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.